जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 255 प्रभात उदयपुर, शुक्रवार 18 जुलाई, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

राहुल गांधी ने एक बार फिर पूर्व आई.ए.एस. अधिकारियों के लिए अपनी कमज़ोरी जाहिर की

सैंथिल, पूर्व आई.ए.एस. अफसर व दलित, जो तमिलनाडू से सांसद भी हैं, अब राहुल की कोर कमेटी में दूसरे स्तम्भ बने

- वेणुगोपाल, सैंथिल व राज्य के प्रभारी, अब राज्य में चुनाव के बारे में अंतिम निर्णय लेंगे।
- कुछ समय पूर्व तक के. राजू भी इस ग्रुप के महत्वपूर्ण सदस्य हुआ करते थे, पर अब के. राजू को झारखण्ड का इन्चार्ज बनाने के बाद, सैंथिल सर्वेसर्वा हो गये हैं, कांग्रेस के दलित एजेण्डा के बारे में।
- पार्टी में जिलाध्यक्षों को असीमित पावर देकर जिला पार्टी को पुनजीर्वित करने का प्लान भी सैंथिल के दिमाग की उपज है। इस प्लान के अनुसार जिलाध्यक्ष को प्रदेशाध्यक्ष को ''रिपोर्ट'' करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सीधा हाईकमान द्वारा नियुक्त होता है। इस नई व्यवस्था में पी.सी.सी. अध्यक्ष व राज्य की इकाई कमज़ोर होगी, यह शायद सोचा नहीं गया। तथा इस नई व्यवस्था से कांग्रेस के संगठन में काफी कंफ्यूज़न फैलने की आशंका है।
- राहुल गांधी के अन्य प्रिय चहेते, कानूनगोलू को बिहार में सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है, तथा यह सर्वे ही टिकट वितरण का आधार बनेगा। पर यह स्मरण करने की भी आवश्यकता है, कि महाराष्ट्र व हरियाणा के चुनाव के समय यह जिम्मेदारी कानूनगोलू को सौंपी गई थी। उन्होंने यह जिम्मेदारी इतनी खूबसूरती से निभाई कि कांग्रेस दोनों राज्यों में बुरी तरह हारी।
- एक अन्य नेता आंध्र के चैला वमाशी चान्द देडडी को जिलाध्यक्ष के चयन व उनके काम काज का विश्लेषण व मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी दी गई है। वे भी वेणुगोपाल के साथ हैं।

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 17 जुलाई। कहा जा रहा है कि शशिकांत सैंथिल राहुल गांधी के करीबी सर्कल में सबसे ताक़तवर लोगों में से एक हैं। वे और के.सी. वेणुगोपाल मिलकर रणनीति, काम-काज और चुनाव संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं।

यहाँ तक कि बहुप्रचारित चुनाव प्रबंधन समिति, जो काफी चर्चा में रही थी और जिसकी अध्यक्ष प्रियंका गांधी बनने वाली थीं, उसे अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, संभवत: प्रियंका को इतने हाई-प्रोफाइल पद से दूर रखने के लिए। अब चुनाव से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श और निर्णय वेणुगोपाल, सैंथिल और संबंधित राज्य के प्रभारी मिलकर करते हैं।

वेणुगोपाल ने ज्यादातर शक्तियाँ अपने पास केन्द्रित कर ली हैं और उनके साथ सैंथिल हैं, जो सभी निर्णयों को क्रियान्वित करने का कार्य कर रहे हैं।

सैंथिल राहुल गांधी के नए चहेते हैं। वे एक पूर्व आई ए एस अधिकारी और दलित हैं, तथा तमिलनाडु से लोकसभा सांसद भी हैं।

के. राजू, जो एक अन्य प्रभावशाली पूर्व आई ए एस अधिकारी और दलित हैं, भी एक समय राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे हैं। दोनों ने दलित एजेंडा को पार्टी में आगे बढ़ाने का काम किया है और कांग्रेसजनों का कहना है कि राहुल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह बाद

जयपुर, 17 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह बाद रखी है। जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की एकलपीठ ने ये आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर दिए। सॉलिसिटर जनरल आर. डी. रस्तोगी, जिन्हें बुधवार को ही केस आवंटित हुआ था, कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, इसलिए प्रकरण की सुनवाई टाली जाने का अनुरोध किया गया। इस पर कोर्ट ने अगले सप्ताह सुनवाई रखने के आदेश दिए।

- गत दिनों ईडी कोर्ट ने महेश जोशी को जमानत देने से इन्कार कर दिया था। उसके बाद ईडी ने जोशी तथा डेढ़ दर्जन अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था।

महेश जोशी की जमानत याचिका में अधिवक्ता स्नेहदीप ने अदालत को बताया कि जोशी को इस प्रकरण में फंसाया गया है। प्रकरण को लेकर एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया। इसके बाद बिना कोई परिस्थिति बदले याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा, ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हैल्थ इन्श्योरैंस पर लगे जी.एस.टी. में भारी कमी आएगी

हैल्थ व लाइफ इन्श्योरैंस पर जी.एस.टी. 18 प्रतिशत से घटाकर 5 से 12 प्रतिशत करने की सोच उभरी है

- इस सोच के अनुसार, यह भी संभव है, कि कुछ कैटेगरीज़, जैसे सीनियर सिटिज़न को इन्श्योरैंस पॉलिसी पर ''ज़ीरो'' जी.एस.टी. कर दी जाये।
- सोच का मकसद है, हैल्थ इन्श्योरैंस सस्ता होगा, तो हैल्थ इन्श्योरैंस का काम छोटे शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ेगा तथा 2027 तक हैल्थ इन्श्योरैंस के कवरेज में सभी नागरिकों को ले लेने के लक्ष्य तक पहुंचना संभव हो सकेगा।
- हैल्थ इन्श्योरैंस से जुड़े सभी संस्थाओं व लोगों ने इस सोच की आगे बढ़कर, भूरि-भूरि प्रशंसा की है।
- इन लोगों का कहना है, हैल्थ इन्श्योरैंस एक लग्ज़री नहीं है, जो कुछ लोगों को उपलब्ध है, बल्कि एक अधिकार है, जो सभी नागरिकों को मिलना चाहिये।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जुलाई। भारत के बीमा क्षेत्र के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण साबित हो सकता है। गुड्स एण्ड सर्विसेज़ टैक्स (जी.एस.टी.) काउन्सिल जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाले भारी 18 प्रतिशत जी.एस.टी. को घटाने की तैयारी में है। यदि आगामी बैठक में यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इससे पॉलिसीधारकों का आर्थिक बोझ कम होगा और पूरे देश में बीमा कवरेज में बड़ा इज़ाफा हो सकता है।

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, काउन्सिल अगस्त के मानसून सत्र के बाद बैठक कर सकती है, बशर्ते कि रेट रैशनलाइज़ेशन (दरों में सुधार) के लिए गठित मंत्री समूह की प्रमुख रिपोर्टें पूरी हो जाएं।

जिस समय पर यह निर्णय आयेगा, वो बहुत ही अहम है। भारत में वार्षिक चिकित्सा मुद्रास्फीति (मैडिकल इन्फ्लेशन) 14 प्रतिशत तक पहुंच गई है, और बीमा प्रीमियम हर साल 20-25 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मौजूदा 18 प्रतिशत जी.एस.टी. आम मध्यमवर्गीय और निम्न आय वाले परिवारों के लिए असंतुलित बोझ बन गया है। बीमा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि एक ऐसे देश में, जहाँ केवल 40 प्रतिशत से कम लोगों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'भारत वहीं से ऑयल खरीदेगा, जहां से उसे ''बैस्ट ऑफर'' मिलता है?

भारत ने नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे की टिप्पणी पर, अपनी ''ऑयल परचेज नीति'' स्पष्ट की

- भारत ने यह स्पष्ट करते समय, यह सावधानी रखी, कि ट्रम्प की रूस से ऑयल खरीदने वाले देशों पर, 100 प्रतिशत अधिक टैरिफ लगाने की धमकी को सीधे संबोधित नहीं किया।
- भारत ने, पर यूरोपीय देशों के दोहरे मापदण्ड पर जरूर कटाक्ष किया, कि इन देशों ने 2027 तक रूस से गैस खरीदने का हाल ही में अनुबंधन किया, पर भारत के रूस से ऑयल खरीदने पर, उनको आपत्ति है।

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 17 जुलाई। मोदी सरकार की विदेश नीति में बदलाव के संकेत देते हुए, विदेश मंत्रालय ने आज रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति पर अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी पर, अपनी लंबे समय से चली आ रही चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि भारत को जो 'सबसे अच्छा प्रस्ताव' मिलता है, वह उसी के अनुरूप अपनी दिशा तय करता है।

कुछ यूरोपीय देशों को प्रतिबंधों के दोहरे मापदंड अपनाने के बारे में आगाह करते हुए, विदेश मंत्रालय ने बड़ी सावधानीपूर्वक यह रेखांकित किया कि उसकी प्रतिक्रिया महासचिव मार्क रुटे की प्रतिबन्धों की धमकी पर केन्द्रित है, तथा मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का नाम न लेने का विशेष ध्यान रखा, जबकि सबसे पहले यह धमकी ट्रम्प ने ही दी थी।

अमेरिका की ओर से रूसी कच्चे तेल पर द्वितीयक (सेकण्डरी) प्रतिबंध लगाने की धमकी के बीच, भारत ने गुरुवार को जवाब देते हुए कहा कि अपनी ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह सबसे अच्छे प्रस्ताव से प्रेरित है। नई दिल्ली ने प्रतिबंधों के लगाये जाने में दोहरे मापदंडों से भी सावधान रहने को कहा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

निचली अदालतों के कर्मचारी शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर

जयपुर, 17 जुलाई। प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों ने, लंबे समय से कैडर पुनर्गठन की मांग पूरी नहीं करने के विरोध में, शुक्रवार से अनिश्चितकालीन समय तक सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है।

राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रवक्ता योगेश महर्षि ने बताया कि कैडर पुनर्गठन को लेकर हाईकोर्ट की फुल बैंच ने दो साल पहले प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया था। इसके बावजूद, राज्य सरकार की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

- प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारी लंबे समय से कैडर पुर्नगठन की मांग कर रहे हैं।

जिला न्यायालय कर्मचारी संघ के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका की भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी से भारत का रुतबा बढ़ा है

पहली बार विश्व महसूस कर रहा है, भारत की भूमिका भी चीन जितनी ही है, ऑयल खरीद के मामले में

- भारत को चीन के बगल में खड़ा करके, विश्व के समक्ष यह सच्चाई उजागर हुई, कि भारत एक बड़ा व महत्वपूर्ण मार्केट है, जिसकी राय विश्व की इकोनॉमी को प्रभावित करती है।
- पर भारत व चीन की रुस से ऑयल खरीदने की मजबूरी यह है कि, अगर ये दोनों देश चाहें भी तो ऑयल की व्यवस्था वैकल्पिक करना अब इतना आसान नहीं। दोनों देश रुस से अपनी ऑयल की आवश्यकता पूरी करने के बारे में इतना व्यस्त हो गये हैं, कि विकल्प के बारे में कभी सोचा ही नहीं, व्यवस्था करना तो दूर की बात है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जुलाई। एक नया प्रस्ताव सामने आया है जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों से अमेरिका को होने वाले सभी निर्यातों पर 500 प्रतिशत का भारी शुल्क (स्लेजहैमर टैरिफ) लगाने की बात की जा रही है।

इस कदम को रूस पर दबाव बनाने और यूक्रेन युद्ध जारी रखने की उसकी क्षमता को खत्म करने की कोशिश माना जा रहा है।

हालांकि, यह कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकट खड़ा कर सकता है और आर्थिक स्थिरता को भी नुकसान पहुँचा सकता है। इससे अमेरिका के अपने हितों को भी चोट पहुँच सकती है। यह निर्णय तेल की वैश्विक कीमतों को बहुत ऊपर ले जा सकता है और विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है।

लेकिन जैसे-जैसे यूक्रेन युद्ध की स्थिति और गंभीर होती जा रही है, इस तरह के कड़े कदम को लेकर अमेरिका में मजबूत समर्थन बनता जा रहा है और अमेरिका इस मामले में अपने पारंपरिक यूरोपीय सहयोगियों के साथ एकजुट है। यूरोप हर दिन इस युद्ध का असर महसूस कर रहा है क्योंकि रूस धीरे-धीरे यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है।

इसके अलावा, यूक्रेन युद्ध के बहाने यूरोप के पूर्वी हिस्से में तानाशाही और रूसी राजनीति की वापसी देखी जा रही है। हंगरी, जो ईयू का सदस्य है, पर ईयू के नियमों की अनदेखी करता रहा है, और जॉर्जिया अब पश्चिमी यूरोप की लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटकर रूस जैसे तानाशाही शासन की ओर बढ़ता दिख रहा है।

यह प्रस्तावित ''स्लेजहैमर'' टैरिफ अमेरिका को होने वाले निर्यातों पर सीधी मार साबित हो सकता है और इससे तेल खरीदने वाले देश रूसी तेल से दूरी बनाने को मजबूर हो सकते हैं। यह कदम खासतौर पर दो देशों को ध्यान

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमरनाथ यात्रा मार्ग पर भारी बारिश से भूस्खलन

नई दिल्ली, 17 जुलाई। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड के बाद गुरुवार को अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। गंदेरबल जिले में बालटाल मार्ग पर रायलपथरी के निकट हुए लैंडस्लाइड में जोधपुर की महिला श्रद्धालु की मौत हो गई। हादसे में तीन यात्री घायल हो गए। इससे बालटाल और पहलगाम के आधार शिविरों से यात्रा रोक दी। भूस्खलन के बाद यात्रा मार्ग पर सैकड़ों लोग फंस गए हैं। रायलपथरी और ब्रारमर्ग के बीच भूस्खलन में फंसे 500 से अधिक तीर्थयात्रियों को सेना ने निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

- हादसे में जोधपुर की सोना देवी की मौत हो गई व 3 अन्य घायल हो गए हैं।

परिजनों के अनुसार, जोधपुर के चांदपोल के बाहर बड़ी भील बस्ती निवासी सोना देवी आठ जुलाई को बस से श्रद्धालुओं के एक जत्थे के साथ अमरनाथ महादेव के दर्शन के लिए निकली थीं। उनके साथ नौ अन्य महिलाएं भी थीं। दर्शन के बाद लौटते

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सहकारिता में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल'

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दादिया में सहकार व रोजगार उत्सव को संबोधित किया

- केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया गया।
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार नया कोऑपरेटिव कोड लाने की दिशा में कार्य कर रही है।
- दादिया के कार्यक्रम में अमित शाह ने विभिन्न गोदामों व आउटलैट्स का वर्चुअल लोकार्पण किया तथा कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित किये।

जयपुर, 17 जुलाई। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत को समृद्ध, सुरक्षित और विकसित बना रहे हैं। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक और पहलगाम के कायराना हमले के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूत किया गया।

शाह गुरूवार को जयपुर के दादिया में सहकार एवं रोजगार उत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अल्प समय में ही बहुत काम किए हैं। राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर पेपरलीक माफियाओं के खिलाफ सख्त संदेश दिया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में लगभग 35 लाख करोड़ रूपये से अधिक के एमओयू हुए, जिनमें से लगभग 3 लाख करोड़ के एमओयू पर काम भी शुरू हो चुका है। शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान, सहकारिता में नवाचारों को अंगीकार करते हुए बेहतरीन काम कर रहा है तथा देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो चुका है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। राज्य सरकार सहकारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर के दादिया गांव में आयोजित सहकार एवं रोजगार उत्सव में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वागत किया। इस अवसर पर शाह ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रूपये का ऋण और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को 2346 माइक्रो एटीएम वितरण किए।

ब्रिटेन में 16 साल पर मिलेगा मताधिकार

इंग्लैंड, 17 जुलाई। कीर स्टार्मर के नेतृत्व वाली ब्रिटेन सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, मतदान करने की उम्र सीमा घटाकर 16 वर्ष करने का फैसला किया है। सरकार ने ऐलान किया है कि ब्रिटेन में अब अगले आम चुनावों में सभी 16 और 17 साल के किशोर भी वोट डाल सकेंगे। बता दें कि ब्रिटेन में मतदान की उम्र में आखिरी बार बदलाव 1969 में हुआ था, जब इसे 21 से घटाकर 18 साल किया गया था। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की सरकार ने कहा कि इस बदलाव को संसद की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये सरकार 16-17 साल के युवाओं को भी अपनी बात रखने का मौका देगी। इस उम्र के बहुत सारे युवा पहले ही सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

- ब्रिटेन की सरकार ने कहा, इस तरह से युवाओं को मुख्य राजनीतिक धारा से जुड़ने का मौका दिया जाएगा।

उप प्रधानमंत्री एंजेला रेयनर ने कहा कहा कि हम आयुसीमा से जुड़े बदलाव लागू कर युवाओं को मुख्य राजनीतिक धारा से जुड़ने का बड़ा मौका दे रहे हैं।